Impact Factor (QJIF): 8.47 E-ISSN: 2583-1615, P-ISSN: 3049-3498

International Journal of Research in Academic World

Received: 04/January/2026 **IJRAW:** 2026; 5(2):117-118 **Accepted:** 14/February/2026

सूक्ष्म, लघु और मध्यम संस्थानों हेतु सरकार के नवाचार

[*1]डॉ. हेमंत कडूणिया

[*1]सहायक आचार्य, लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी, सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा, राजस्थान, भारत।

सारांश

भारत का $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का विकसित उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम संस्थान (MSME) वर्ग की तेज़ी पर टिका है। प्रस्तुत आलेख सरकार की विभिन्न योजनाओ की जानकारी प्रदान करता है। CGTMSE (सूक्ष्म और लघु संस्थान के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) जोकि MSMEs और स्टार्टअप्स को कवर करता है, के द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले संस्थानों को फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP), एक खास क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी पहल है, जो छोटे संस्थान बनाकर शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के स्व-रोजगार को बढ़ावा देती है। RAMP प्रोजेक्ट (MSME परफॉर्मेंस को बढ़ाना और तेज़ करना) वर्ल्ड बैंक से पोषित एक पहल है, जिसे भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम संस्थान मंत्रालय और तेलंगाना सरकार के उद्योग विभाग के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। मज़बूत बैंकिंग नवाचार, बदलती साख स्कीम और ALEAP जैसे वर्ल्ड क्लास इनक्यूबेटर के साथ, यह वर्ग मज़बूत विकास के लिए तैयार है।

मुख्य शब्द: सूक्ष्म, लघु और मध्यम संस्थान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, रैम्प योजना, ALEAP संस्थान आदि।

प्रस्तावना

वर्तमान मे बड़े उद्योगों के साथ MSME की अहमियत को पहचाना गया है क्योंकि यह अलग-अलग सामाजिक आर्थिक मकसद जैसे ज़्यादा आर्थिक विकास और रोज़गार, आउटपुट, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और एक्सपोर्ट को बढ़ावा और सपोर्ट देने में अहम योगदान देता है। MSME किसी भी देश के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। MSME सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास अपने योगदान के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह वर्ग देश के तेज़ और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास की दिशा में बहुत ज़रूरी है। MSME सेक्टर देश की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के उस टारगेट को पाने में मदद कर सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग 2022 तक भारत की GDP में 25% का योगदान दे। इस मकसद के लिए, भारत सरकार ने "मेक इन इंडिया" की एक अच्छी पहल की है। यह आलेख MSME के परफॉर्मेंस और ग्रोथ और मौकों पर फोकस करता है।

भारत का $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का विकसित उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम संस्थान (MSME) वर्ग की तेज़ी पर टिका है। यह नवाचार और रोजगार सृजन के इंजन की तरह काम करता है, लेकिन साख, तकनीकी सहायता और बाजार संबंध तक सीमित पहुँच के कारण इसके विकास की राह में अक्सर चुनौतियाँ आती हैं। ALEAP (एसोसिएशन ऑफ़ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ़ इंडिया, हैदराबाद) जैसे संगठन इन चुनौतियों को दूर करने में सबसे आगे रहे हैं, खासकर महिलाओं के नेतृत्व वाले संस्थानों के लिए, जिसमें कार्यभार, वित्त, मेंटरशिप और सरकारी पॉलिसी और स्कीम के साथ मुख्य सहभागिता शामिल है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम संस्थान (MSME) वर्ग से संबधित योजनाए

भारत सरकार ने MSMEs की साख, नवाचार और बाजार संपर्क की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई ज़रूरी पॉलिसी, उपाय और स्कीम शुरू की हैं। उनमें से एक, CGTMSE (सूक्ष्म और लघु संस्थान के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट(Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) जोकि MSMEs और स्टार्टअप्स को कवर करता है। सूक्ष्म और लघु संस्थानों के लिए, ऋण कवर 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे अगले 5 सालों में साख में और 1.5 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कवर ऋण राशि का 90% तक पहुँच गया है, जिससे 27 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले संस्थानों को फायदा हुआ है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP), एक खास क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी पहल है, जो छोटे संस्थान बनाकर शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के स्व-रोजगार को बढ़ावा देती है। PMEGP एंटरप्रेन्योरशिप प्रशिक्षण को 50 लाख रुपये (मैन्युफैक्चरिंग) या 20 लाख रुपये (सर्विस सेक्टर) तक के प्रोजेक्ट के लिए 35% तक

***Corresponding Author:** डॉ. हेमंत कडूणिया

मार्जिन मनी सब्सिडी से जोड़ता है। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और ग्रामीण युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। PMEGP सीधे फाइनेंशियल इनक्लूजन और रोजगार सृजन से जुड़ा है, और इसके कोष को हर साल बदला जाता है ताकि बड़े सेक्टर तक पहुंच पक्की हो सके।

जनवरी 2025 में शुरू हुई MCGS-MSME (म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम) MSME के लिए 100 करोड़ रुपये तक का बिना गारंटी वाला लोन देती है, जिसमें संयंत्र, मशीनरी और व्यवसाय विस्तार की खरीद पर फोकस किया जाता है। गारंटी कवरेज 60% है, जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) देती है। इस स्कीम के तहत मंज़ूर किए गए ऋण पर पहले साल कोई गारंटी फीस नहीं लगती है।

उद्यम पोर्टल में रजिस्टर्ड सूक्ष्म संस्थान पहले साल में 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की लिमिट वाले नए MSME क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र हैं।

MSME के प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज़ करना - विश्व बैंक समर्थित परियोजना

RAMP प्रोजेक्ट (MSME परफॉर्मेंस को बढ़ाना और तेज़ करना) वर्ल्ड बैंक से पोषित एक पहल है, जिसे भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम संस्थान मंत्रालय और तेलंगाना सरकार के उद्योग विभाग के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। ALEAP तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में RAMP प्रोजेक्ट को लागू कर रहा है। प्रोजेक्ट, "SHGs और स्टार्टअप्स को MSMEs में बदलना" तेलंगाना राज्य के 33 जिलों में लागू किया जा रहा है।

यह प्रोजेक्ट 1,500 महिला स्वयं सहायता समूह और 500 स्टार्टअप्स को MSMES में बदलकर उन्हें मज़बूत बनाने के लिए है, जिससे 15,500 लाभान्वित प्रभावित होंगे। इस पहल के ज़रिए, ALEAP का मकसद महिला एंटरप्रेन्योर्स को संसाधन, एंटरप्रेन्योरशिप और कोशल विकास प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग सहायता, तकनीक, क्रेडिट और बाजार संपर्क देना है, ताकि वे छोटे समूहों से सस्टेनेबल व्यवसाय में बदल सकें।

आंध्र प्रदेश के 22 ज़िलों में "महिला व्यवसाय विकास सेवा प्रदाता बनाना" नाम का एक खास प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है, जिसका टारगेट 1,200 महिला व्यवसाय विकास सेवा (Business Development Service) प्रदाता बनाना है।

यह प्रोजेक्ट जागरूकता बढ़ाने, क्षमता बढ़ाने और MSMEs को ज़रूरी व्यवसाय विकास सेवा तक पहुँचने में मदद करने के लिए फील्ड लेवल के व्यवसाय फैसिलिटेटर का एक कैडर तैयार करने पर फोकस करता है। इन सर्विस में सरकारी स्कीम, सब्सिडी और अनुलाभ, मार्केटिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन (ZED), प्रोजेक्ट फ़ीज़िबिलिटी रिपोर्ट और पर्यावरणीय और सामाजिक अनुपालना पर दिशा निर्देश शामिल हैं।

RAMP प्रोजेक्ट, महिला एंटरप्रेन्योर्स को MSME इकोसिस्टम में ज़्यादा सक्रियता से जोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित है।

चुनौतियाँ और अवसर

भारत के MSME को कम कार्यशील पूंजी, अनुपालना की ज़रूरतों, तकनीकों को अपनाने और बाजार के उतार-चढ़ाव से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मज़बूत बैंकिंग नवाचार, बदलती साख स्कीम और ALEAP जैसे वर्ल्ड क्लास इनक्यूबेटर के साथ, यह वर्ग मज़बूत विकास के लिए तैयार है। मैं महिला एंटरप्रेन्योर और MSME से नए डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, सरकारी योजनाओ, व्यवसाय इनक्यूबेशन सेंटर और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाने की अपील करता हूँ। नवाचार करने, पूंजी पाने और दुनिया भर में फैलने का मौका पहले कभी इतना बड़ा नहीं था।

संदर्भ

1. Katyal A, Xaviour B. A study on MSMEs'-role in propelling economic development of India & a discussion on current HR issues in MSMEs' in India. *Int J Sci Res Publ.* 2015;5(2):1-11.
2. Shiralashetti AS. Prospects and problems of MSMEs in India-A study. *Int J Multidiscip Acad Res.* 2012;1(2):1-7.
3. Zanjurne P. Growth and future prospects of MSME in India. *Int J Adv Eng Manage Sci.* 2018;4(8):608-614.
4. Financial Express. Banking & finance. Available from: https://epaper.financialexpress.com/4059553/Banking-finance/Banking-finance#page/28/2